भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2407
मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर

†2407. श्री एम. के. राघवनः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी बैंकों के लिए एकल सॉफ्टवेयर शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केरल राज्य सरकार ने इस एकल एकीकृत सॉफ्टवेयर पर कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि भारत सरकार द्वारा पीएसीएस के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण देने के बावजूद केरल राज्य सरकार ऐसे ऋणों पर ऊंची ब्याज दर वसूल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या नाबार्ड पीएसीएस के माध्यम से राजसहायता प्राप्त दरों पर किसानों को सीधे ऋण संवितरित कर सकती है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): जी हाँ मान्यवर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपनी विकासात्मक भूमिका के तहत ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को वर्ष 2011 में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) से जुड़ने में सुविधा प्रदान की थी। नाबार्ड ने 2 सीबीएस क्लाउड की सुविधा दी है, अर्थात टीसीएस बैंक्स (130 बैंक) और फिनेकल (81 बैंक)। वर्तमान में, नाबार्ड इन बैंकों को अपनी सीबीएस प्रणाली को उन्नत करने में भी सुविधा प्रदान कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने 13 मार्च, 2013 और 11 सितंबर, 2013 के परिपत्रों के माध्यम से सभी शहरी सहकारी बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) अपनाने का आदेश दिया है। यह निर्देश यूसीबी क्षेत्र के भीतर परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए आरबीआई की पहल का हिस्सा है।

(ख): भारत सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें देश में सभी पैक्स को एक सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना और उन्हें एसटीसीबी और डीसीसीबी के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है।

इस समय, परियोजना के तहत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 67,009 PACS के लिए मंजूरी दी गई है। 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हार्डवेयर खरीदा गया है। कुल 25,674 PACS को ERP सॉफ्टवेयर पर जोड़ा गया है और 15,207 PACS लाइव हो गए हैं। हालाँकि केरल सरकार ने आज तक PACS के कम्प्यूटरीकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ग): नाबार्ड ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूचित किया है कि, केरला/ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां ऐसे ऋणों पर उच्च ब्याज दर नहीं वसूल रही हैं, जिनके लिए भारत सरकार ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है।

(घ): नहीं, शासनादेश के अनुसार, नाबार्ड सीधे पैक्स को ऋण उपलब्ध नहीं करा सकता है। नाबार्ड जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को ऋण पुनर्वित्त करता है :

*****